भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3103

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

अर्थ गंगा योजना का कार्यान्वयन और कैराना के निकट यमुना नदी घाट का विकास

3103. सुश्री इकरा चौधरीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अर्थ गंगा योजना के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं और इसके छह कार्यक्षेत्रों का विवरण क्या है;

(ख) क्या सरकार अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कैराना के निकट यमुना नदी घाट का विकास या पुनरुद्धार करने की योजना बना रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत प्रदूषण की समस्या को दूर करने और यमुना नदी के किनारे सतत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, जिनमें प्राकृतिक खेती और जलज जैसी पहलें शामिल हैं;

(घ) यमुना नदी संरक्षण के संदर्भ में गंगा प्रहरियों की भूमिका और आईएमअवतार तथा सीएलएपी जैसी पहलों सहित जन भागीदारी बढ़ाने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या यमुना नदी के किनारे नदी संरक्षण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में योजना की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): अर्थ गंगा एक सतत और व्यवहार्य आर्थिक विकास मॉडल है जो एक आर्थिक सेतु के माध्यम से नदी-जन संपर्क को मज़बूती प्रदान करता है। अर्थ-गंगा के मुख्य स्तंभों में प्राकृतिक जल-संरचना को बढ़ावा देना; एसटीपी से उपचारित जल और गाद का मुद्रीकरण और पुन: उपयोग; आजीविका के अवसरों में सुधार और पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना शामिल है।

(ख): कैराना, शामली जिले में यमुना नदी पर घाट के विकास का कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) में विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ): प्रदूषण की समस्या से निपटने और गंगा बेसिन में सतत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, एनएमसीजी ने जलज केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र नदी पुनरुद्धार के लिए आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।

एनएमसीजी ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से गंगा बेसिन राज्यों में प्राकृतिक कृषि करने वाले किसान के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

एनएमसीजी ने जल और ऊर्जा उपयोग, मृदा उर्वरता और फसल उत्पादकता पर प्राकृतिक कृषि के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वालमतारी (जल और भूमि प्रबंधन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान), आंध्र प्रदेश को "जल और ऊर्जा बचत पर प्राकृतिक कृषि प्रथाओं का मूल्यांकन और मृदा उर्वरता और फसल उत्पादकता में वृद्धि" शीर्षक से एक अध्ययन परियोजना को मंजूरी दी है।

पतंजलि को "पौधों के संरक्षण, प्रशिक्षण और क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु गंगा तटों के निकट पुष्प जैव विविधता की खोज" नामक एक परियोजना अधिकृत की गई है। यह एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य गौमुख (उत्तराखंड) से गंगा सागर (पश्चिम बंगाल) तक गंगा नदी पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है।

"जलज: अर्थ गंगा को साकार करने के लिए नदी और लोगों को जोड़ना" परियोजना के अंतर्गत, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून ने इको-पर्यटन, सामुदायिक भागीदारी और संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए डॉल्फिन सफारी, होमस्टे, आजीविका केंद्र और जागरूकता एवं बिक्री केंद्र आदि जैसे विभिन्न मॉडलों पर जलज केंद्र स्थापित किए हैं।

एनएमसीजी ने हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन (हेस्को) को "प्रौद्योगिकी आधारित सामुदायिक एवं स्थानीय संसाधनों के लाभ उठाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम " नामक एक परियोजना स्वीकृत की है। इसके अंतर्गत देहरादून (उत्तराखंड) में एक अर्थ गंगा केंद्र और प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), दिगवारा (बिहार) और साहेबगंज (झारखंड) में तीन गंगा संसाधन केंद्र स्थापित किए गए । वित्त वर्ष 2024-25 में हेस्को द्वारा विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 8,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

एनएमसीजी ने 'उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग' के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा प्रकाशित की है। यह रूपरेखा राज्य को पुन: उपयोग नीति तैयार करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है और इसका उद्देश्य उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए उपयुक्त बाजार और आर्थिक मॉडल तैयार करना है। उपचारित जल के पुन: उपयोग के लिए विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (इंटैक) ने अपने अध्ययन के अंतर्गत वास्तुशिल्पीय प्राकृतिक और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण हेतु सभी गंगा जिलों

का मानचित्रण किया है । यमुना बेसिन के लिए भी इस तरह के दस्तावेजीकरण हेतु एक अध्ययन शुरू किया गया है।

जन भागीदारी बढ़ाने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, एनएमसीजी गंगा बेसिन में स्थापित जलज केंद्रों के माध्यम से जैव विविधता और नदी पुनरुद्धार पर जागरूकता बढ़ा रहा है। ये केंद्र नमामि गंगे कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाते हैं और गंगा बेसिन के विभिन्न जलजों /स्वयं सहायता समूहों/गैर सरकारी संगठनों को बाज़ार संपर्क प्रदान करते हैं । गंगा बेसिन में नदियों की जैव विविधता और स्वच्छता की रक्षा और संरक्षण हेतु स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षित स्थानीय समुदाय के सदस्यों को गंगा प्रहरियों के रूप में तैनात किया गया है।

आजीविका और जन भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अर्थ गंगा पहल को बढ़ावा देने के लिए 'आई एम अवतार' के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

कन्टिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी प्वाइंट (सीएलएपी) एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन क्विज़ और संदर्भ सामग्री के माध्यम से पर्यावरण, जल और नदियों से संबंधित मुद्दों पर ज्ञान के लिए एक मंच प्रदान करना है।

गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के प्रयासों में जनता में ज़िम्मेदारी और सहभागिता की भावना जगाने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इनमें गंगा उत्सव, नदी उत्सव, नियमित सफाई अभियान और वृक्षारोपण अभियान, घाट पर योग, गंगा आरती आदि शामिल हैं। इन प्रयासों को गंगा प्रहरी, गंगा विचार मंच आदि जैसे समर्पित गंगा रक्षकों का भी समर्थन प्राप्त है ।

(ङ): अर्थ गंगा के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर की जाती है, जिसमें जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त कार्य बल भी शामिल है।

*****